supplementary has nothing to do with the main question.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: He has not come prepared. He is trying to pass on the burden to somebody else.

MR. CHAIRMAN: Question is about labour and now you are asking about a sick mill.

SHRI J. VENGAL RAO: Sir, I know better than Shri Satyanarayan Reddy. I have been the Chief Minister of that State. I know about this Bajrang Jute Mill. But his supplementary is unconcerned with this question. (*Interruptions*)

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Please come with preparation. Otherwise, do not take the responsibility of answering the question.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Sir, the hon. Minister had been the Chief Minister of Andhra Pradesh for quite a long time.

(*Interruptions*)

He has said that it is not possible for the Central Government to take it over. His statement has come in the Press too. He cannot deny it now.

SHRI J. VENGAL RAO: Sir, if the State Government is ready to take over, we will take it over under the IDR Act.

मध्य प्रदेश में सीमेंट कारखानों के आनुषंगिक उद्योग

*391. **श्री अजीत जोगी** † :
ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में 20 से अधिक बड़े और छोटे सीमेंट कारखाने स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सीमेंट कारखानों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब तक कितने आनुषंगिक उद्योग स्थापित किये गये हैं ।

† सभा में यह प्रश्न श्री अजीत जोगी द्वारा पूछा गया ।

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) सीमेंट उद्योग मूलत: एक प्रक्रिया उद्योग है, जिसे चूने के पत्थर, जिप्सम, कोयले आदि जैसी मुख्य निविष्टियों की आपूर्ति के लिये सहायक एककों से सहायता की आवश्यकता नहीं होती है । फालतू पुर्जों की आवश्यकता के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि देश के भीतर इनकी पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है । जिस मामले में कोई एकाधिकार किस्म का कम्पोनेन्ट उपलब्ध नहीं होता है तथा उसके आयात के बारे में सरकार को कोई विशिष्ट प्रस्ताव मिलता है तो उस पर आयात नीति के उपबन्धों के अनुसार गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है । सीमेंट के जूट और सिंथेटिक से बुने या दोनों ही से बनी बोरियों मे पैक किया जाता है । देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की बोरियों का विनिर्माण करने की पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है अत: इनकी कमी के बारे में सीमेंट कारखानों से कोई शिकायत नहीं मिली है ।

श्री अजीत जोगी : मान्यवर, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में सीमेंट के बड़े और छोटे संयन्त्र हैं । सौभाग्य और दुर्भाग्य से यह ऐसी जगह हैं जहां ज्यादातर आदिवासी और हरिजन आबादी है । हुआ यह है कि इन संयन्त्रों के लगने के बाद स्थानीय लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिला है । न तो उनके एंसीलियेरी यूनिट्स बनाए गये है और जहां स्थानीय लोगों को सीमेंट के प्लांट बनाने के लिए विस्थापित किया गया है वहां यह आश्वासन दिया गया था कि जितने परिवार विस्थापित हों उन में से कम से कम एक परिवार के एक व्यक्ति को इन्हीं सीमेंट प्लांटस में रोजगार दिया जायेगा, इसकी पूर्ति नहीं हुई है । अभी हमने सरसरी तौर पर एक सर्वेक्षण कराया था और केवल 25 प्रतिशत लोगों को इस तरह इन से इन

सीमेंट प्लांट्स में रोजगार दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो गरीब आदिवासी और हरिजन इन सीमेंट प्लाट्स के लगने के कारण विस्थापित हुए हैं उनके पुनर्वास के लिए और खास तौर से उनके परिवारों में से एक आदमी को रोजगार देने के लिए शासन के द्वारा क्या किया जा रहा है और कब तक यह स्थिति बनेगी कि इन सब को कम से कम हर परिवार के एक एक आदमी को रोजगार मिल जाएगा ?

SHRI M. ARUNACHALAM: Sir, I agree that Madhya Pradesh is one of the major cement-producing States. There are about 13 big units, 11 mini cement uits and one white cement unit. We have given licences to about 13 new units which have to be established.

In regard to employment of poor Harijans and other people, we do not have any complaints so far. If the hon. Member....

श्री अजीत जोगी : मैंने कई बार लिखा है ।

SHRI M. ARUNACHALAM: If the hon. Member brings this to our notice we will take it up with the concerned industries and try to solve the problme.

श्री अजीत जोगी : मान्यवर, जवाब ही नहीं आया है ।

MR. CHAIRMAN: His question is about giving preference to those who are displaced. He wants to know whether the industries will provide employment to these people.

(*Interruptions*)

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): Sir, there are now 32 cement plants. Out of this, only are three public sector units under the Cement Corporation of India. The remaining are private units. Sir, you know very well that Madhya Pradesh is producing 20 per cent of the total cement production in the country. Certainly, they will get employment both direct and indirect. We will issue instructions.

SHRI AJIT P. K. JOGI: They are not getting employment. They are taking people from outside

SHRI J. VENGAL RAO: We will issue instructions to give first preference to the local people.

MR. CHAIRMAN: So far as your own plants are concerned..

SHRI J. VENGAL RAO: Only three plants are there.

MR. CHAIRMAN: His point is that a promise was made that from among those who are displaced, at least one man from each family will be given employment.

SHRI J. VENGAL RAO: I will look into that.

MR. CHAIRMAN: You will see to it?

SHRI J. VENGAL RAO: Yes.

MR. CHAIRMAN: The Minister has accepted your proposition.

SHRI AJIT P. K. JOGI: Thank you, Sir. Now, my second supplementary is: यह जो सीमेंट प्लांट्स हैं इनके कोई न कोई एंसीलियेरी यूनिट्स बनने चाहिये और ब्यूरो आफ पब्लिक इंटरप्राइजेज की यह इंस्ट्रक्शंस हैं कि एंसीलियेरी यूनिट्स स्थानीय लोगों को ही दिये जाने चाहिए । पहली बात तो यह हुई है ।

श्री सभापति : आप सीमेंट कारपोरेशन की ही बात कीजिए ।

श्री अजीत जोगी : केवल सीमेंट की ही बात कर रहा हूं । पहली बात तो यह है कि एंसीलियेरी यूनिट्स स्थापित नहीं किये जा रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कब तक स्थापित किये जाएंगे । दूसरी बात यह है कि एंसीलियेरी यूनिट्स स्थापित होंगे क्या शासन यह गारंटी देगा कि उस में स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी ? और तीसरी बात यह है अभी तक ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइस की इंस्ट्रक्शन है कि यह एन्सिलरी यूनिट स्थानीय लोगों को देना चाहिए तो इसका पालन क्यों नहीं होना चाहिए ? अभी भी स्पेयर पार्ट्स मध्य प्रदेश के बाहर से थोक में खरीद कर लाये जा रहे हैं । ऐसा क्यों हो रहा है और इसको कब तक रखा जायेगा ?

MR. CHAIRMAN: Will you give preference to local industries in establishing ancillary industries? That is the question.

SHRI J. VENGAL RAO: In cement plants there is less scope for anciallary industries. (*Interruptions*). Let me answer, let me complete my answer. The major inputs for cement plants are limestone, gypsum, coal and all these things. There is no question of ancillary industry. There are only three or four item for which ancillary industries may be necessary.

श्री अजीत जोगी : अभी भी बाहर से करोड़ों रुपये की सालाना खरीद हो रही है । मेरा सजेशन है कि वहां के लोग बनाये और उन्हीं से खरीदा जाये ।

I have statistics with me.

SHRI J. VENGAL RAO: If the people are ready to manufacture,..certainly..

MR. CHAIRMAN: Will you give them preference?

SHRI J. VENGAL RAO: Yes, we will certainly give them preference.

श्री सुरेश पचौरी: मैं आपके माध्यम से मंत्री जी यह जानना चाहूंगा कि जैसा कि इन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि सीमेंट की पैकिंग के लिए जूट सिंथेटिक वोवन आदि की आवश्यकता होती है जिसकी कमी के सम्बन्ध में सीमेंट उद्योगपतियों ने लिखा है लेकिन मेरी अपनी जानकारी के अनुसार इस प्रकार की कमी है इस बात का उल्लेख मध्य प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को किया है उनकी नालिज में लाया गया है । केन्द्रीय सरकार को क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव मिला है यदि मिला है तो इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये गये ? साथ ही मध्य प्रदेश में जो सीमेंट के लिए लाइमस्टोन, जिप्सम, कोयला आदि की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए क्या प्रयास केन्द्रीय सरकार के द्वारा किये गये और क्या इस सम्बन्ध में कोई फाइनेन्शियल एसिस्टेंस देने की केन्द्रीय सरकार की योजना है ?

MR. CHAIRMAN: Have you received a proposal for the State Government in this context? Also, if there are local people who want to do it, is there any scheme of helping them?

SHRI J. VENGAL RAO: We have not received any proposal from the State Government. There is no dearth of jute bags and plastic bags also. There is sufficient availability of...

SHRI SURESH PACHOURI: State Government has already written.

MR. CHAIRMAN: He says that he has not received. We cannot have dispute over that.

श्री नरेश सी० पुगलिया : सभापति महोदय देश में सीमेंट की कमी को देखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना में उस समय की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस उद्योग के लिए काफी प्रोत्साहन दिया और देश में खासकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सीमेंट के बड़े उद्योग काफी बड़े पैमाने पर आये है : लेकिन उन उद्योगपतियों ने उद्योग खोलने के बाद सरकार से पूरी सुविधा लेने के बाद इस उद्योग के कारण जो एयर पोल्यूशन होता है उससे उसका असर पांच किलोमीटर के रेडियस के अंदर होता है और वहां पर जो किसानों की जमीन पड़ती है वह उपजाऊ जमीन बंजर हो चुकी है और इन किसानों की शिकायतें राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को बता दी । लाइसेंस देते समय कंडीशन है कि सीमेंट उद्योग में उल्टी पाल्यूशन इक्विपमेंट लगाना बहुत जरूरी है और इनके न लगाने की वजह से ही भारी मात्रा में पाल्यूशन हो रहा है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि जिन इंडस्ट्रीज ने ये इक्विपमेंट नहीं लगाये हैं उनके लगवाने के लिए सरकार क्या कोई कार्यवाही कर रही है और फिर मेरा दूसरा सवाल है कि इस सीमेंट उद्योग में जो नये प्रोजेक्ट्स आये है इनमें सीमेंट वेज बोर्ड के मुताबिक पहले साल में 75 परसेंट और दूसरे साल 100 परसेंट पगार वेज बोर्ड के हिसाब से मजदूरों को मिलनी चाहिए । लेकिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बड़े बड़े पूंजीपति और उद्योगपति इनको लागू नहीं कर रहे है । इंडिस्ट्रयल डिपार्टमेंट द्वारा लाइसेंस देते समय इस सिलसिले में दो कंडीशंस हैं मैं जानना चाहता हूं कि आप इस पर क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

SHRI J. VENGAL RAO: About wage Board recommendations, I have no in-

formation now. About the setting up of industries...

MR. CHAIRMAN: You give the answer about anti-pollution.

SHRI J. VENGAL RAO: Anti-pollution is the function of State Government. They must enforce this. As far as Government units are concerned, we have issued orders.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: There is the Central Pollution Board which is supposed to monitor it. Sir, he is totally diverting....

MR. CHAIRMAN: Let him answer.

SHRI J. VENGAL RAO: One of the conditions of the licence is that they must apply this anti-pollution equipment and as far as possible, our Government has also issued orders to the Cement Corporation units to implement these anti-pollution measures.

SHRI AJIT P. K. JOGI: But they have not implemented it anywhere.

SHRI NARESH C. PUGLIA: What about the Wage Board recommendations?

MR. CHAIRMAN: Wage Board does not come under him.

SHRI NARESH C. PUGLIA: When they are issuing the licence, this is one of the conditions. That is why I am asking.

SHRI J. VENGAL RAO: No, Sir, wage Board condition is not there.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Yes, the condition does exist that unless the Pollution Board clears it, they are not supposed to issue the licence.

SHRI J. VENGAL RAO: She is quite right Sir that without environmental clearance they cannot set up a plan.

SHRIMATI RENUKA CHOWHURY: Sir, this is the biggest pollution factor in this House, and the State Government has not cleared him either. I can say that on authority.

MR. CHAIRMAN: There is no pollution factor in this House.

श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर : माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में जो प्राकृतिक सम्पदा का भण्डार है उसको देखकर उसकी तरफ लालायित होकर विभिन्न प्रांतों के बड़े बड़े उद्योगपति उद्योग स्थापित करने पहुचते हैं और इसका स्वागत है। वहां के लोकल लोग जो इन उद्योगों की वजह से विस्थापित होते हैं वे वहां के, प्रदेश के रहवासी होने के नाते उन उद्योगों में इम्प्लाइमेंट प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हू कि क्या वे इसके लिए कोई आश्वासन देंगे या इसके लिए कोई प्रतिशत फिक्स करेंगे कि जो भी एक्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है या जिनको लाइसेंस देने वाले हैं, चाहे, किसी भी विभाग में हों, किसी भी वस्तु से संबंधित हों उनमें वहां के लोकल लोगों को एक फिक्स परसेंटज के तहत इम्लायमेंट देने की व्यवस्था करेंगे ?

SHRI J. VENGAL RAO: Sir, it is mandatory on the units because we have issued general instructions to give employment to local people. Nobody will go there for marrying limestone and all those things. For unloading and loading, the local people will get employment.

MR. CHAIRMAN: Question No. 392. Absent. Question No. 393. Absent.

*392. [*The questioners (Shri Krishna Kumar Birla and Shri V. Narayansamy) were absent. For answer* vide *col.* 37 infra]

*393. [*The questioner (Dr. Nagen Saikia) was absent. For answer* vide *col.* 37 infra.]

Question No. 394.